नंदिग्राम टाईम्स

RNI NO. MAHHIN/2016/69743 EDITOR : SHAIKH JAHUR AHEMAD

Friday 2nd, January 2026 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 247 | ● पृष्ठ 04 | ● मूल्य - 2 रूपए | ● www.nandigramtimes.com

'नहीं खत्म होगी रूस-युक्रेन की जंग', पुतिन ने दिया बड़ा बयान; क्या ट्रंप की कोशिश हो गई नाकाम?

नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन के रुख से वहां पर लड़ाई खत्म होने की तस्वीर बनती नहीं दिख रही है। इसलिए यूक्रेन में लड़ाई चालू हुए वर्ष में भी जारी रह सकती है।

युद्ध में बलिदान करने वाले और लड़ रहे योद्धाओं की कौशल की प्रशंसा करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस बहादुरी और विजय में विश्वास रखता है। रूसी राष्ट्रपति ने यह बात अपने नववर्ष के संबोधन में कही है।

पुतिन ने कहा यूक्रेन में लड़ाई इस वर्ष भी जारी रहेगी
पुतिन के लिए 31 दिसंबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तिथि को रूस की सत्ता संभालते हुए उन्हें 26 वर्ष पूरे हुए हैं।

पुतिन का यह बयान तब आया है जब बीते रविवार को फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की युद्ध समाप्ति पर वार्ता हुई है और छह जनवरी को उनकी यूरोपीय नेताओं से वार्ता होनी है।

इस बीच जेलेंस्की ने भी कहा है कि वह रूस के आगे समर्पण नहीं करेंगे। वह शांति चाहते हैं लेकिन यूक्रेन के हितों को ध्यान में रखते हुए सम्मानजनक स्थिति में ही समझौता करेंगे।

इस बीच यूक्रेन के बाद यूरोपीय संघ ने भी कहा है कि शांति के लिए हो रही वार्ता को विफल करने के लिए ही रूस ने पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले की कोशिश का शिगूफा छोड़ा है। वास्तव में पुतिन यूक्रेन युद्ध खत्म करना ही नहीं चाहते हैं।
सीआइए को नहीं मिला पुतिन के आवास पर हमले का साक्ष्य, अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए ने रूस के उस दावे का खंडन किया है कि जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति के नोवगोरोद स्थित आवास पर 28-29 दिसंबर की रात 91 ड्रोनों से हमले की कोशिश की थी। एजेंसी ने कहा है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे रूसी दावे की पुष्टि हो। जवाब में रूस ने कहा है कि वह जल्द ही यूक्रेनी हमले के ठोस साक्ष्य अमेरिका को सौंपेगा।
(न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

'उनके खालीपन को नहीं भरा जा सकता', खालिदा जिया के निधन पर पीएम मोदी का इमोशनल लेटर

नई दिल्ली: बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 30 दिसंबर 2025 की सुबह निधन हो गया। बेगम खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी वहां पहुंचे थे। एस. जयशंकर ने जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश सौंपा था।

खत में पीएम मोदी ने खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनके जाने से जो खालीपन है, उसे भरा नहीं जा सकता। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेगम खालिदा जिया के जाने से एक ऐसा खालीपन आया है जिसे भरा नहीं जा सकता, लेकिन उनका विजन और विरासत हमेशा रहेगी।
चिट्ठी में लिखा है, 'मुझे यकीन है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के आपके काबिल नेतृत्व में उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया जाएगा और एक नई शुरुआत और भारत और बांग्लादेश के बीच गहरी और ऐतिहासिक साझेदारी को और बेहतर बनाने के लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करेंगे।' पीएम मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं बांग्लादेश के लोगों के साथ भी हैं, जिन्होंने अपने पूरे इतिहास में जबरदस्त ताकत और सम्मान दिखाया है। उन्होंने लिखा, 'मुझे भरोसा है कि वे शांति और सद्भाव के साथ आगे बढ़ते हुए अपने साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और राष्ट्रीय एकता की गहरी भावना से आगे बढ़ते रहेंगे।'

'अनोखे इरादे और विश्वास वाली नेता थीं'
पीएम मोदी ने खालिदा जिया के साथ 2015 में अपनी मुलाकात को याद किया और कहा, 'वह एक अनोखे इरादे और विश्वास वाली नेता थीं और उन्हें बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त था।' पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के विकास में खालिदा जिया ने अहम भूमिका निभाई। खालिदा जिया ने बांग्लादेश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में कई अहम योगदान दिए।

'उनकी आत्मा को शांति मिले'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'इस गहरे निजी नुकसान पर मेरी दिल से संवेदनाएं स्वीकार करें। उनकी आत्मा को शांति मिले।' उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे तारिक रहमान और उनके परिवार को इस मुश्किल समय से उबरने की ताकत और हिम्मत दें। उन्होंने कहा, "मैं आपके भविष्य के प्रयासों के लिए भी आपको शुभकामनाएं देता हूं।' 31 दिसंबर को उन्हें उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के कब्र के पास सुपुर्द-ए-खाक किया गया। बेगम जिया को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। जिया के जाने के साथ ही बांग्लादेश में राजनीतिक युग का अंत हो गया।

ऑपरेशन सिंदूर में DRDO के हथियारों ने दिखाई जबरदस्त ताकत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बड़ी जानकारी

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) द्वारा विकसित हथियार प्रणाली ने निर्णायक भूमिका निभाई, जिससे भारत की सुरक्षा क्षमता और स्वदेशी तकनीकी श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से सामने आई।

दिल्ली में DRDO के 68वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि DRDO के उपकरणों ने ऑपरेशन में बिना रुकावट के काम किया, जिससे सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ा और मिशन की सफलता सुनिश्चित हुई। उन्होंने वैज्ञानिकों और कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि यह साबित करता है कि DRDO कितनी समर्पित और पेशेवर संस्था है।

साथ ही रक्षा मंत्री ने 'सुदर्शन चक्र' परियोजना का भी उल्लेख किया और कहा कि DRDO जल्द ही इसे विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह एक महत्वाकांक्षी हवाई रक्षा प्रणाली है, जिसका लक्ष्य अगले दशक में देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सम्पूर्ण हवाई सुरक्षा प्रदान करना है।

राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि DRDO अब केवल हथियार विकसित करने वाला संगठन नहीं रह गया है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी निर्माता और भरोसेमंद साथी बन गया है। उन्होंने निजी उद्योग, स्टार्टअप और अकादमिक संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भी जोर दिया, ताकि भारत की रक्षा तैयारियाँ और अधिक सुदृढ़ हों।

इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि भारत न केवल सैन्य रूप से सक्षम बन रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में भी निरंतर प्रगति कर रहा है।

'सिर पर पेट्रोल डालकर जला दिया', बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी पर बर्बर हमला; पत्नी ने बताई पूरी बात

ढाका। बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में नए साल की पूर्व संध्या पर एक हिंदू व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया। 50 वर्षीय खोकन चंद्र दास पर हमलावरों ने धारदार हथियारों से वार किया, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से घायल खोकन ने पास के तालाब में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। वे फिलहाल ढाका के अस्पताल में जीवन-मृत्यु से जूझ रहे हैं।

यह घटना 31 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे दामुद्या उपजिले के कोनेश्वर यूनियन में केउरभंगा बाजार के पास हुई। खोकन चंद्र दास दवा की दुकान और मोबाइल बैंकिंग का कारोबार चलाते हैं। दुकान बंद करके घर लौटते समय हमलावरों ने उन्हें घेर लिया, बुरी तरह पीटा और चाकू से गोद दिया। इसके बाद सिर व चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

मैं सरकार से मदद की गुहार लगाती हूं-पीड़ित की पत्नी
पीड़ित की पत्नी सीमा दास ने एनडीटीवी से कहा, "हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा कि मेरे पति को अचानक क्यों निशाना बनाया गया। उन्होंने हमलावरों में से दो को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने सिर और चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।" रोते हुए सीमा ने आगे कहा, "हम हिंदू हैं, बस शांति से जीना चाहते हैं। हमलावर मुस्लिम थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। मैं सरकार से मदद की गुहार लगाती हूं।"

सीमा दास ने बताया कि खोकन की एक आंख की सर्जरी हो चुकी है और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। उनके तीन बच्चे हैं और स्थिर करने के लिए कम से कम छह यूनिट खून की जरूरत है। अस्पताल में बात करते समय वे अपने सबसे छोटे बेटे को कसकर पकड़े हुए थीं।

पुलिस जांच और पहचान
स्थानीय मीडिया 'प्रोथोम आलो' के अनुसार, पुलिस ने दो हमलावरों की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। दामुद्या पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा कि मामला जांच के दायरे में है। कुछ स्थानीय लोगों ने इसे सांप्रदायिक नहीं बताया, लेकिन इलाके में व्याप्त डर स्पष्ट दिख रहा है—अधिकांश लोग नाम गुप्त रखने की गुजारिश कर रहे हैं।

अल्पसंख्यकों पर हमलों की बढ़ती घटनाएं
यह हमला पिछले दो हफ्तों में हिंदुओं पर चौथा बड़ा हमला है। दिसंबर में दीपू चंद्र दास को ईशनिंदा के झूठे आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और शव को आग लगा दी। इसी तरह अमृत मंडल और बजेंद्र बिस्वास की हत्या हुई। मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हिंसा में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मानवाधिकार संगठनों ने 2025 में सैकड़ों हमलों की रिपोर्ट दी है, जिसमें मंदिरों पर हमले, लूटपाट और आगजनी शामिल हैं।

नए साल पर MP को बड़ा तोहफा: 20 से अधिक शहरों में 'सुगम लोक परिवहन सेवा' से सरकारी बसें लौटेंगी

NEWS AGENCY

भोपाल: नए साल 2026 में मध्यप्रदेश की सड़कों पर सरकारी बसों का परिचालन एक बार फिर शुरू होने जा रहा है, जिसे राज्य सरकार ने जनता को बड़ा तोहफा बताया है। इस नई सेवा का नाम 'सुगम लोक परिवहन सेवा' रखा गया है, जो राज्य के 20 से अधिक शहरों को जोड़कर यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा देगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया है कि यह सेवा पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर संचालित होगी, जिससे बस टर्मिनल, स्टेशन और अन्य ढांचागत सुविधाओं का निर्माण भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने ₹101 करोड़ से अधिक अंशपूंजी को मंजूरी दी है, ताकि योजना तेजी से लागू की जा सके।

वर्तमान में राज्य के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन कंपनियाँ हैं, जिनमें से 16 पहले से सक्रिय हैं। इन्हें अब सात संभागीय कंपनियों में मर्ज कर एक स्टेट-लेवल होल्डिंग कंपनी के नियंत्रण में लाया जाएगा। इससे बस संचालन अधिक संगठित और पारदर्शी होगा। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में लोगों को बेहतर यातायात व्यवस्था मिले और मध्यप्रदेश का सार्वजनिक परिवहन फिर से मजबूती से सड़कों पर लौटे.

छत्रपति संभाजीनगर चुनाव 2026: संजय शिरसाट ने बीजेपी पर वार, कहा – कार्यकर्ताओं से भागना बड़ी गलती

छत्रपति संभाजीनगर: महापालिका चुनाव 2026 के मद्देनज़र शिवसेना (शिंदे गुट) के पालकमंत्री संजय शिरसाट ने भाजपा पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजप नेतृत्व कार्यकर्ताओं से भाग रहा है और युती को तोड़ने में उसका हाथ है, जिससे स्थानीय राजनीति में तनाव बढ़ा है। शिरसाट ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने रात्रि-दिन पार्टी के लिए काम किया, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नेताओं को कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना आवश्यक है और उनसे पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। इस बयान से संभाजीनगर का चुनावी माहौल और गरमाया है।

IPL 2026 विवाद: जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने शाहरुख खान पर लगाया 'देशविरोधी' आरोप, बांग्लादेशी खिलाड़ी केकेआर में लेने को बताया बड़ी गलती

नागपुर: आगामी आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल करने के फैसले को लेकर देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। इसी बीच जगत्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने टीम के सह-स्वामी और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शाहरुख का चरित्र संदिग्ध और देशहित के खिलाफ रहा है, और यह निर्णय ''देशविरोधी'' प्रवृत्ति का उदाहरण है।
रामभद्राचार्य ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारतीय लीग में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे भारत के हित में नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के फैसले ''गद्दार'' जैसे रवैये को दर्शाते हैं और देशभक्ति सर्वोपरि होनी चाहिए।

शाहरुख खान पर क्यों भड़के जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य?

इस बयान के साथ ही अन्य धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों ने भी शाहरुख खान और केकेआर पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने शाहरुख को ''गद्दार'' तक कह दिया और कहा कि ऐसी गतिविधियाँ देशवासियों की भावनाओं के खिलाफ हैं। विवाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में फैल चुका है, जहाँ कुछ लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, तो कई वर्ग इसे राष्ट्रीय भावना पर चोट मान रहे हैं। KKR या BCCI की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह मुद्दा न केवल क्रिकेट स्तर पर चर्चा का विषय बना है, बल्कि खेल, राजनीति और राष्ट्रीयता के बीच नए बहस को जन्म दे रहा है।

छत्रपति संभाजीनगर में राजनीतिक विवाद: भाजपा उम्मीदवार के 'बी-फॉर्म' को छिपाने का आरोप, वीडियो वायरल होने से Election Office में हड़कंप

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): आगामी महानगरपालिका चुनाव 2026 के नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक गंभीर आरोप सामने आया है। भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) की एक महिला उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि निवडणूक निर्णय अधिकारी ने उसका आधिकारिक 'बी-फॉर्म' (B-Form) जानबूझकर छिपा दिया, जिसके कारण उसे अपक्ष (Independent / अस्वीकृत) घोषित कर दिया गया और पार्टी का चुनाव चिन्ह 'कमल' भी नहीं दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

सूत्रों के अनुसार, जब महिला उम्मीदवार ने अपना बी-फॉर्म समय पर जमा किया और वह निर्वाचन कार्यालय में स्वीकार भी कर दिया गया, तब भी उसे मुख्य दस्तावेज का हिस्सा नहीं बनाया गया। बाद में जब उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, तो उसका नाम अपक्ष उम्मीदवारों की श्रेणी में दिखा, जिससे स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष और असंतोष उत्पन्न हुआ।

इस मामले को लेकर वायरल वीडियो में पार्टी के कार्यकर्ता अधिकारियों से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वे कहते हैं, "हमने फॉर्म समय पर दिए, तो उसे क्यों स्वीकार नहीं कर के नामांकन में जोड़ा गया?" स्थानीय कार्यकर्ता अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

भाजपा की महिला उम्मीदवार का कहना है कि वह अनुसूचित जाति से हैं और उनके फॉर्म को छिपा देने से उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर किया गया और उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास लिखित शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया है, जिसमें व्हायरल वीडियो को सबूत के रूप में पेश किया जाएगा।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घटना केवल एक तकनीकी विवाद नहीं है, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर प्रश्न उठाती है। ऐसे आरोपों से लोकल चुनाव आयोग की जवाबदेही और चुनाव अधिकारियों के निर्णयों की समीक्षा की जरूरत भी उजागर होती है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और क्या इस मामले में कोई अदा जांच या पदाधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाया जाएगा।

महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ

नंदिग्राम टाईम्स

Friday 2nd, January 2026 वर्ष - 9 , अंक 247 , पृष्ठ 03

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ग्रहण किए बप्पा के आशीर्वाद, चुनावी रण-भूमि में बढ़ाई उम्मीदें

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर का दर्शन कर भगवान गणेश से राज्य और जनता के कल्याण की कामना की। यह धार्मिक अनुष्ठान उस समय हुआ है जब महानगरपालिका चुनाव 2026 का चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, और राजनीतिक दल आगामी मतभेदों में अपनी मजबूत स्थिति बनाना चाहते हैं।

फडणवीस के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मंदिर पहुँचें, जहाँ उन्होंने बप्पा के चरणों में फूल-मालाएँ अर्पित कर जनता की खुशहाली, सामाजिक सौहार्द और महायुति गठबंधन की सफलता के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि गणेश जी का आशीर्वाद महापालिका चुनावों में भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों को विजय दिलाएगा।

राज्य में राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हैं, और उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया तथा प्रचार अभियान चरम पर पहुँच चुका है। इसी पृष्ठभूमि में फडणवीस ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह दर्शन किया, जिससे उनके समर्थकों में उत्साह और उम्मीदों का संचार हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने से जनता के बीच सकारात्मक संदेश जाता है, और यह लोक-भावनाओं तथा चुनावी रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है।

सिद्धिविनायक मंदिर को गणपति के आशीर्वाद का प्रमुख केन्द्र माना जाता है, जहाँ मुख्यमंत्री का यह धार्मिक कार्यक्रम आगामी राजनीतिक फैसलों और परिणामों पर असर डाल सकता है।

NWMC ELCTION 2026 | नांदेड में भाजपा-शिवसेना युती पर अशोक चव्हाण का बड़ा बयान:

नांदेड में भाजपा-शिवसेना युती पर अशोक चव्हाण का बड़ा बयान: 25-30 सीटों की मांग पर युती नहीं बनी, हम शहर का सर्वांगीण विकास करेंगे

नांदेड: 15 जनवरी 2026 को होने वाले महाराष्ट्र के 29 महानगरपालिका चुनावों के बीच नांदेड का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। इस बीच राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के साथ चुनावी गठबंधन न होने के पीछे के कारणों को साफ शब्दों में बताया है। चव्हाण ने कहा कि भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना को शुरुआत में 8-10 सीटें देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन शिवसेना ने इसके बदले 25-30 सीटों की मांग की, जो संभव नहीं थी। इस वजह से दोनों दलों के बीच युती नहीं हो पाई है।

चव्हाण ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा का प्राथमिक लक्ष्य नांदेड का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि शहर को आज कई मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बढ़ती ट्रैफिक कंजेशन, बुनियादी सुविधाओं में कमी और सुचारू विकास की आवश्यकता शामिल है।

ऐसी परिस्थितियों में भाजपा स्थानीय जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टिकट आवंटन को लेकर जिन नागरिकों पर पार्टी ने दांव लगाया है वे "निवाचनीय और क्षेत्र के लिए काम करने वाले" हैं, न कि वित्तीय भुगतान या किसी अन्य कारण से चुने गए हैं।

चव्हाण ने आगे कहा कि भाजपा ने नांदेड के लिए अपना जाहीरनामा पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें पार्टी की विकास योजनाओं, केंद्र-राज्य सरकार की उपलब्धियों और स्थानीय मुद्दों के समाधान शामिल हैं। उनका मनना है कि भाजपा खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी और जनता से सीधे समर्थन की अपील करेगी।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि statewide राजनीति में भी गूंजेंगे। गठबंधन न होने से भाजपा और शिवसेना-एकनाथ शिंदे दोनों को अपनी-अपनी रणनीतियाँ तेज करनी होंगी। राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार, गठबंधन की गोलबंदी में विफलता से स्थानीय मुद्दों पर बहस और भी अधिक केंद्रित हो सकती है, जिससे मतदाता चरणों पर अलग तरह से सोच सकते हैं।

चव्हाण के बयान ने स्पष्ट किया है कि भाजपा की प्राथमिकता स्थानीय विकास और जनता की बेहतरी है और वह इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना चाहती है। ऐसे में नांदेड महापालिका चुनाव एक स्वतंत्र चुनाव जैसा वातावरण बनकर उभर रहा है, जहां पक्ष अपने दम पर जीत हासिल करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

पुणे PMC चुनाव में अजीबोगरीब मामला: शिंदे शिवसेना का 'AB फॉर्म' गायब, दस्तावेज़ अंत तक नहीं लौटा

बर्फ में बदल गया वासुकि ताल, बर्फ में बदल गया वासुकि ताल,

पुणे: 2026 के पुणे महानगरपालिका (PMC) चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक अनोखी और विवादास्पद घटना सामने आई है। ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक उम्मीदवार को शिंदे शिवसेना का आधिकारिक 'AB फॉर्म' मिला, लेकिन वह अंत तक वापस नहीं लौटा, जिससे चुनावी प्रक्रिया में खलबली मच गई है।

यह घटना तब सामने आई जब शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) द्वारा उम्मीदवारों को उनके पार्टी के आधिकारिक AB फॉर्म (अधिकारीक प्रत्याशी फॉर्म) दिए जा रहे थे। हालांकि, कुछ वार्डों में एक ही सीट के लिए दो अलग-अलग उम्मीदवारों को AB फॉर्म दिए जाने की सूचना मिली, जिससे गड़बड़ी और विवाद पैदा हो गया। इसके बाद एक उम्मीदवार ने अपने प्रतिद्वंद्वी का AB फॉर्म छीन लिया और उसे गायब कर दिया, जो अंततः फॉर्म अंत तक वापस नहीं मिला।

इस विशेष मामले में, धनकवड़ी-सहकारनगर इलाके के वार्ड नंबर 26 में हुई घटना ने स्थानीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पार्टी के स्थानीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच अंतरिक मतभेद और उमेदवार चयन की असमंजस ने इस घटना को जन्म दिया। पार्टी के एक दावेदार ने प्रतिद्वंद्वी के फॉर्म को फाड़कर निगलने तक की कोशिश की, जिससे चुनावी प्रक्रिया की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और पुलिस को भी तात्कालिक हस्तक्षेप करना पड़ा।

स्थानीय नेताओं ने इस घटना को पार्टी की अंदरूनी पूर्णता और समन्वय की कमी बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे शिंदे शिवसेना की चुनावी तैयारी में गंभीर अशांति और असमंजस के रूप में प्रस्तुत किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे विवाद चुनावी माहौल और प्रबंधन पर बड़ी चोट लगाते हैं और वोटरों के बीच भरोसे को कमजोर कर सकते हैं।

यह मामला पुणे में चुनावी संघर्ष की जटिलता और उग्र रूप को दर्शाता है, जहाँ उम्मीदवारों और पार्टियों के बीच टिकट वितरण और नामांकन प्रमाणपत्रों के मुद्दों ने अप्रत्याशित रूप धारण किया है। चुनाव अधिकारी इस पर नजर रखे हुए हैं और आगे की कार्यवाही के लिए स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं।

अकोला महापालिका चुनाव: 27 सीटों पर वंचित आघाड़ी का प्रतिनिधित्व नहीं, — 53 प्रत्याशी चुनावी रिंगण में

संवाददाता |

अकोला: 2026 के अकोला महानगरपालिका चुनाव में राजनीतिक गतिविधियाँ अपने चरम पर हैं, लेकिन एक दिलचस्प स्थिति उभर कर सामने आई है। वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA) ने कुल 53 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, फिर भी 27 वार्डों में उसके कोई उम्मीदवार नहीं हैं, जिससे स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

वंचित बहुजन आघाड़ी ने शहर के पश्चिमी हिस्से के 32 वार्ड और पूर्वी हिस्से के 21 वार्ड में अपने प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन चार वार्डों सहित कुल 27 सीटों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे वार्डों में VBA के उम्मीदवार न होने से यह स्पष्ट नहीं है कि पार्टी इन सीटों पर किस तरह रणनीति अपनाएगी, खासकर नामांकन वापसी और चिन्ह आवंटन की प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इन खाली सीटों पर रणनीतिक निर्णय भविष्य में चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। यदि VBA अन्य दलों से समर्थन या tacit समझौता करती है, तो चुनावी समीकरण बदल सकता है। वहीं, स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन इलाकों में कथित वोट विभाजन से अन्य प्रमुख दलों को लाभ मिल सकता है। चुनावी माहौल में भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस सहित अन्य बड़े दल भी सक्रिय हैं और अपनी ताकत आज़मा रहे हैं। ऐसे में VBA का यह चयनात्मक प्रतिनिधित्व स्थानीय मतदाताओं और राजनीतिक रणनीतियों पर आगे असर डाल सकता है।

मुंबई महापालिका चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे की चार-घंटे बैठक, गठबंधन रणनीति और प्रचार योजना पर बातचीत

मुंबई: आगामी मुंबई महानगरपालिका (BMC) और अन्य निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच दो प्रमुख राजनीतिक हस्तियों — शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे-गुट) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे — के बीच चार घंटे लंबी बैठक हुई। यह मुलाकात राज के निवास 'शिवतीर्थ' में हुई, जहां दोनों नेताओं ने महापालिका चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में दोनों दलों की युती के तहत चुनाव प्रचार, घोषणापत्र (मैनिफेस्टो) और संयुक्त रणनीति पर बातचीत की गई है। चर्चा का मुख्य फोकस आगामी चुनाव में भाजपा और महायुति गठबंधन को कड़ा मुकाबला देना और मराठी मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक विकल्प प्रदान करना था। बैठक में प्रचार सभाओं, रैलियों और पार्टी घोषणा कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार हुआ।

राज और उद्धव ठाकरे की यह मुलाकात इस लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ समय में दोनों दलों के बीच साझा मंच बनाने की अटकलें तेज़ हो रही थीं, और चुनाव निकट आते ही यह कदम राजनीतिक भूगोल पर असर डाल सकता है। चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि Yुती के स्थानीय स्तर पर बगावत या असहमति उत्पन्न होने वाले मामलों से निपटने के उपायों पर भी विचार किया गया।

राजकीय विश्लेषकों का मानना है कि ठाकरे बंधुओं की यह बैठक न सिर्फ दोनों दलों के सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि चुनाव के आख़िरी चरणों में एक साझा चुनावी रणनीति तैयार करने में भी मदद कर सकती है। इससे पहले दोनों पक्षों ने संयुक्त घोषणापत्र जारी करने की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य मतदाताओं के बीच अपनी प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट रूप से पेश करना है।

मुंबई महापालिका सहित राज्य के अन्य नगर निगमों में होने वाले चुनावों के मद्देनज़र यह बैठक राजनीतिक हलकों में रणनीतिक बदलाव का संकेत मानी जा रही है, जिससे आगे के चुनावी समीकरणों पर असर पड़ सकता है।

छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी उम्मीदवारों के आवेदन खारिज, निर्दलियों का समर्थन पार्टी के लिए चुनौती

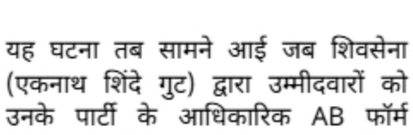

छत्रपति संभाजीनगर: महापालिका चुनाव 2026 में नामांकन पत्रों की छानबीन के दौरान कई राजनीतिक दलों के अधिकृत उम्मीदवारों के आवेदन त्रुटियों के कारण खारिज कर दिए गए हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया में नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। चुनाव अधिकारियों ने छोटे-छोटे तकनीकी कारणों से कई उम्मीदवारों के नामांकन को अवैध घोषित किया, जिससे पार्टियों में खलबली मची है।

जहाँ दलों के अधिकृत उम्मीदवारों के आवेदन रद्द किए गए हैं, वहाँ अब राजनीतिक पार्टियाँ निर्दलीय (अपक्ष) उम्मीदवारों को समर्थन देने पर विचार कर रही हैं ताकि निर्दलियों को पार्टी चिन्ह के बिना भी मुकाबला मजबूत किया जा सके। जटिल आवेदन प्रक्रिया और कागज़ात की कमी के चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे पार्टियों को अब विकल्प तलाशने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

सुषमा आंधारे ने बोला बड़ा बयान: बीजेपी टूट रही है, सुप्रिया सुळे ने कहा 'दोनों राष्ट्रवादी एक साथ हैं'

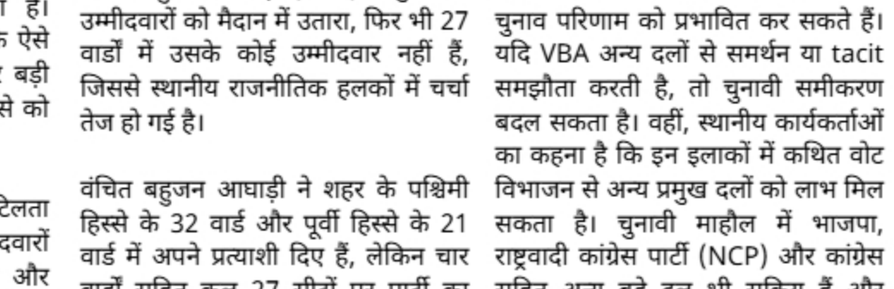

मुंबई: महाराष्ट्र में महापालिका चुनाव 2026 के बीच राजनीति की हलचल तेज है। इसी माहौल में शिवसेना (ठाकरे) की नेता सुषमा आंधारे ने भाजपा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि "भाजपा फुटी की कगार पर है" क्योंकि गठबंधन के अंदर विभिन्न मतभेद उभर रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच असहमति स्पष्ट दिखाई दे रही है। आंधारे के अनुसार, भाजपा में अब कोई एकजुट नेतृत्व नहीं बचा है और पार्टी की स्थिति कमजोर होती जा रही है।

वहीं, एनसीपी नेता सुप्रिया सुळे ने कहा है कि दोनों राष्ट्रवादी गुट (शरद पवार और अजित पवार) अब एक साथ हैं और उन्होंने महापालिका चुनाव में साझा रणनीति पर काम करने की बात कही है। सुळे का कहना है कि युति स्पष्ट रूप से हो चुकी है और इसके तहत उम्मीदवारों को लेकर जानकारी इकठ्ठा की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी ने चुनाव के लिए गठबंधन निर्णय को सर्वसम्मति से लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान स्थानीय निकाय चुनावों के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं।

भाजपा और विपक्षी गठबंधनों के बीच की इस टकराहट ने चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। इस चुनावी परिवेश में जहां भाजपा के आंतरिक मतभेद चर्चा में हैं, वहीं सुळे का दावा है कि राष्ट्रवादी गुट एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है और वे जनता के बीच अपनी योजनाओं को लेकर प्रचार करेंगे।

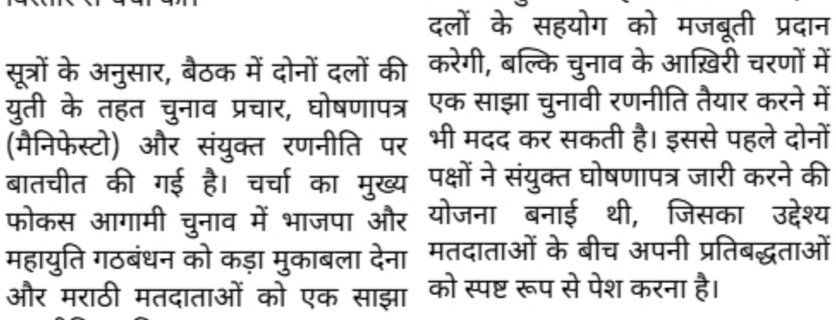

धनंजय मुंडे को बड़ी राहत: बीड कोर्ट ने चुनाव हलफनामे छिपाने वाली याचिका खारिज की

मुंबई/बीड: महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को बड़ी कानूनी राहत मिली है। बीड जिले की अदालत ने करुणा मुंडे द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुंडे ने 2024 के विधानसभा चुनाव के नामांकन हलफनामे में जानकारी छिपाई थी। न्यायालय ने पाया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं और यह भी नहीं सिद्ध हुआ कि किसी तथ्य को छिपाने का मकसद चुनाव जीतना था।

इस फैसले से मुंडे को राजनीतिक और कानूनी दबाव से राहत मिली है, और अब उनके देवेंद्र फडणवीस सरकार में एक बार फिर मंत्री बनने की संभावनाएँ मजबूत हो गई हैं। अदालत ने ध्यान दिया कि किसी भी छिपाई गई जानकारी का 2024 के चुनाव परिणाम पर असर नहीं पड़ा और याचिका कानून के तहत आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। यह मामला पिछले दिनों राजनीति और मीडिया में व्यापक चर्चा में रहा है, और अदालत के फैसले के बाद मुंडे की स्थिति और स्थिर होने की उम्मीद है।

नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर

नंदिग्राम टाईम्स

Friday 2nd, January 2026 वर्ष - 9 , अंक 247 , पृष्ठ 04

नांदेड़ महानगरपालिका चुनाव: 59 नामांकन पत्र खारिज, 81 सीटों के लिए 878 उम्मीदवार अब मैदान में

नांदेड: आगामी नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका चुनाव की नामांकन पत्रों की छानबीन में 59 उम्मीदवारों के फॉर्म अवैध पाए गए, जबकि 878 आवेदन वैध घोषित किए गए हैं। 31 दिसंबर को संपन्न हुई छानबीन प्रक्रिया में यह निर्णय लिया गया, जिससे अब 81 वार्डों के लिए औपचारिक रूप से 878 उम्मीदवार चुनावी रिंगण में बने हुए हैं।

महापालिका चुनाव के लिए कुल 1203 नामांकन पत्र 23 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच विभिन्न कार्यालयों में जमा किए गए थे। प्रारंभिक चरण में 38, 29 दिसंबर को 265 और अंतिम दिन 30 दिसंबर को 901 अर्ज दाखिल हुए। इन सभी को 31 दिसंबर को सात अलग-अलग निर्णय अधिकारी कार्यालयों में छाना गया।

छानबीन के दौरान कई आवेदन फॉर्म में त्रुटियाँ, आवश्यक दस्तावेजों की कमी और नियमों के उल्लंघन के कारण खारिज कर दिए गए। उन उम्मीदवारों को, जिनके फॉर्म स्वीकार नहीं हुए, अब नामांकन वापस लेने का विकल्प दिया गया है और राजनीतिक दल उन्हें मनाने के प्रयास में जुटे हैं।

कुछ ऐसे भी दावेदार हैं जिन्होंने अलग-अलग पार्टियों के समर्थन से एबी फॉर्म जोड़े, लेकिन उनमें से कुछ की पात्रता भी विवाद में रही। वहीं, मराठवाड़ा जनहित पार्टी ने भी कई वार्डों में मजबूत दावेदार उतारे हैं, जिसमें कुछ पूर्व नगरसेवक और स्थानीय नेता शामिल हैं, जिनके नामांकन पत्र वैध घोषित हुए हैं।

प्रत्येक प्रभाग में अलग-अलग संख्या में आवेदन वैध पाए गए हैं — कुछ वार्डों में बहुत कम फॉर्म खारिज हुए, तो कुछ में अपेक्षाकृत अधिक। अब चुनावी रणनीतियाँ तय करने तथा उम्मीदवारों के प्रचार अभियान पर जोर देने की तैयारी तेज हो गई है।

नांदेड चुनाव विवाद: भाजपा में अंतर्कलह, पूर्व सीएम अशोक चव्हाण पर 50 लाख रुपये लेने के गंभीर आरोप

नांदेड | नांदेड महापालिका चुनाव की तैयारी के बीच भाजपा (BJP) के भीतर एक गंभीर विवाद उभरकर सामने आया है, जिसने स्थानीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। भाजपा सांसद और पूर्व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर एक माजी नगरसेवक ने उमेदवारी के लिए 50 लाख रुपये लेने का खळबळजनक आरोप लगाया है, जिससे पार्टी के अंदरूनी कोलाहल उजागर हुआ है।

भानुसिंह रावत नाम के पूर्व नगरसेवक, जो कभी चव्हाण के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक रहे हैं, ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने बेटे की उम्मेदवारी सुनिश्चित करने के लिए अशोक चव्हाण से 50 लाख रुपये मांगे और स्वीकार किए। रावत ने कहा कि उन्हें बिना कोई स्पष्ट कारण बताए टिकट से वंचित कर दिया गया, जबकि चव्हाण के करीबी अन्य कार्यकर्ताओं को टिकट मिले।

इस असंतोष के चलते उन्होंने सार्वजनिक रूप से भाजपा नेतृत्व की प्रक्रिया और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।

रावत ने यह भी दावा किया कि पार्टी के अंदर favoritism और पैसों के प्रभाव से टिकट वितरण की नीति लागू की जा रही है, जिससे लंबे समय से पार्टी से जुड़े और मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को धोखा मिला है। उन्होंने कहा कि 1980 से वह चव्हाण के साथ सक्रिय थे और भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कई पुराने साथी कार्यकर्ताओं के साथ उम्मीद जताई थी कि उन्हें भी मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
इस आरोप के जवाब में भाजपा नेताओं या चव्हाण ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों के बीच इस मुद्दे ने असंतोष की आग ढाह दी है और इससे भाजपा के उमेदवारी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह के विवाद स्थानीय चुनावों के मैदान में भाजप की छवि को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर तब जब विपक्षी दल इस मुद्दे को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नांदेड की राजनीति पहले से ही सहमति और गठबंधन बदलने की स्थितियों से प्रभावित रही है, और अब यह आरोप पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है।

भाजपा में यह विवाद बताता है कि लोकल नेतृत्व, टिकट वितरण और पारदर्शिता जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति में किस कदर उबलते जा रहे हैं, और आगामी मतदान में इनका प्रभाव किस तरह दिखेगा, यह देखने वाली बात होगी।

कांग्रेस–वंचित गठबंधन में राजनीतिक ‘किरकिरी’, बी-फॉर्म विवाद से बढ़ी खटास

नांदेड में महापालिका चुनाव से पहले कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच बना गठबंधन एक बार फिर राजनीतिक खींचतान का शिकार हो गया है। हाल ही में संपन्न नगर परिषद चुनाव में दोनों दलों के बीच तालमेल बिगड़ा था और अब महापालिका चुनाव के लिए 12 बैठकों के बाद बनी आघाड़ी बी-फॉर्म वितरण के दिन ही नए विवाद में उलझ गई है।

कांग्रेस और वंचित के बीच सेक्युलर विचारधारा को मजबूती देने के उद्देश्य से गठबंधन की बात कही जा रही थी। कई दौर की बैठकों के बावजूद अंतिम समय तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिससे बी-फॉर्म वितरण की पूर्व संध्या पर गठबंधन टूटने की आशंका भी जताई गई। प्रभाग 7 में कांग्रेस के चार उम्मीदवार तय होने के बावजूद वंचित ने दावा ठोका था। लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस ने अंततः यह प्रभाग वंचित को सौंप दिया।

इसके बाद कांग्रेस नेता व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे की उपस्थिति में गठबंधन की औपचारिक घोषणा की गई, जिसमें वंचित द्वारा 20 और कांग्रेस द्वारा 61 उम्मीदवार उतारने का निर्णय बताया गया। लेकिन ऐन मौके पर प्रभाग 18 में वंचित द्वारा दो अतिरिक्त बी-फॉर्म जारी किए जाने से विवाद खड़ा हो गया। इस प्रभाग में कांग्रेस के चार और वंचित के दो उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। इससे पिछले दो दिनों से दोनों दलों के बीच राजनीतिक ‘किरकिरी’ तेज होने की चर्चा है। इससे पहले भी नगर परिषद चुनाव में इसी तरह का विवाद सामने आया था।

नांदेड महापालिका चुनाव 2026: भाजपा ने ‘आम्ही जीतेंगे’ संकल्प के साथ पहला घोषणापत्र जारी, अशोक चव्हाण ने विकास की प्राथमिकता जताई

नांदेड: आगामी महापालिका चुनाव 2026 के लिए नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका में भाजपा ने सबसे पहले अपना जाहिरनामा (घोषणापत्र / संकल्पनामा) जारी किया है, जिसमें पार्टी ने स्पष्ट संकल्प जताया है कि “आम्ही जिंकणारच” – हम जीतेंगे। यह घोषणापत्र भाजपा के राज्य सह-प्रमुख माधव भांडारी तथा वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण की उपस्थिति में नववर्ष के पहले दिन आयोजित समारोह में जनता के समक्ष पेश किया गया।

भाजपा के घोषणापत्र की शुरुआत “चला आता परिवर्तन घडवू या” के नारे के साथ हुई, जिसमें नांदेड शहर के समग्र और संतुलित विकास की दिशा को प्राथमिकता देने की बात कही गई। चव्हाण ने लोगों से अपील की कि वे भाजपा को सत्ता सौंपें ताकि शहर के नियोजन, यातायात, हरित विकास और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर ठोस कार्य किया जा सके।

इस कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की अच्छी-खासी मौजूदगी देखी गई। नांदेड में भाजपा इस बार 81 में से 67 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर उतरी है और पार्टी ने इसका संकल्प प्रबल रूप से जनता के सामने रखा है।

भाजपा का मानना है कि यह घोषणापत्र न केवल योजनाओं का दस्तावेज़ है बल्कि जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और विकास की दिशा को भी रेखांकित करता है। पार्टी की रणनीति के अनुसार इस घोषणा के जरिए वे स्थानीय मतदाताओं का विश्वास जीतना चाहते हैं और चुनावी मुकाबले में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं।

इस पहल से यह संकेत मिलता है कि नांदेड के महापालिका चुनाव में भाजपा की आगामी रणनीति, विकास एजेंडा और चुनावी जोश प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

अमरावती महापालिका चुनाव 2026: बच्चू कडू ने भाजपा पर लगाया टिकट विवाद का गंभीर आरोप

संवाददाता |

अमरावती: आगामी महापालिका चुनाव 2026 के बीच शहर की राजनीतिक गर्माहट बढ़ती जा रही है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू ने भाजपा पर टिकट बंटवारे को लेकर तीखे आरोप लगाए हैं और कहा है कि पार्टी में वफादार कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा की चुनावी रणनीति को आलोचना का निशाना बनाते हुए सवाल उठाया कि ‘‘बायको एक पक्ष में, नवरा दूसरे में लड़ रहा है’’, क्या इससे स्वाभिमान कहीं खो गया है?

बच्चू कडू ने आरोप लगाया कि पार्टी में स्थानीय कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बाहरी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही पार्टी “पैसे वाले उम्मीदवारों” को आगे क्यों बढ़ा रही है और “निष्ठावान कार्यकर्ताओं” को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनके बयान के अनुसार, ऐसे फैसलों से भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है।

कडू ने कहा कि अमरावती जिले में बहुत से स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक पार्टी के लिए सेवा दी, लेकिन पार्टी ने हाल के टिकट वितरण में उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिति भाजपा के अंदर गुटबाजी और असंतोष की ओर इशारा करती है, जो चुनावी माहौल को और जटिल बना सकती है।

नागपुर पूर्व में टिकट विवाद: खोपड़े पिता-पुत्र ने विधायक वंजारी पर बोला हमला

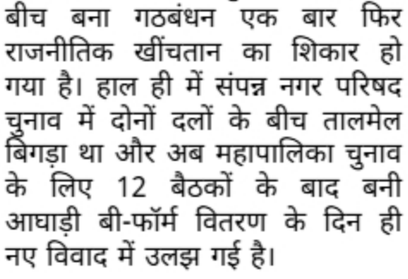

नागपुर: आगामी **महापालिका चुनाव 2026** के मद्देनजर पूर्व नागपुर में राजनीतिक माहौल गरम है। **भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णा खोपड़े और उनके बेटे रोहित** ने कांग्रेस **विधानपरिषद सदस्य अभिजीत वंजारी** पर तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि वंजारी ने रोहित को भाजपा का टिकट न मिलने पर कांग्रेस टिकट की पेशकश कर राजनीतिक सियासत की। खोपड़े पिता-पुत्र का कहना है कि वंजारी के बयान “हास्यापद” हैं और कांग्रेस में घरानेशाही व पुराने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है। रोहित ने कहा कि ऐसे वक्तव्य स्थानीय कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डालते हैं। इस विवाद से चुनावी तनाव बढ़ गया है।

जालना महापालिका चुनाव 2026: कलेक्टर आशिमा मित्तल ने आचार संहिता उल्लंघन पर कड़ा अलर्ट – मतदाताओं को रिश्वत देने-लेने पर सजा तक जेल

जालना: आगामी महापालिका चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच जालना प्रशासन ने आचार संहिता (Model Code of Conduct) संबंधी गंभीर चेतावनी जारी की है। जिल्हाधिकारी एवं महापालिका निर्वाचन अधिकारी आशिमा मित्तल के निर्देश पर 30 से अधिक निगरानी पथक तैनात किए गए हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मतदाताओं को पैसे या अन्य प्रलोभन देकर प्रभावित करना एक गंभीर अपराध है, और इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के तहत दोष सिद्ध होने पर एक वर्ष तक की कैद हो सकती है।

जालना महापालिका में कुल 65 पार्षद पदों के लिए 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 2,45,929 मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार नियमों का उल्लंघन, तोतयागिरी, अवैध व्यय, गलत जानकारी देना, अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन और राष्ट्रीय एकात्मता को प्रभावित करने वाले बयान देना सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। इनमें रिश्वत लेने-देने वाले मामलों पर भी दंड और दंडात्मक मुआवजा शामिल है। आचार संहिता कक्ष के प्रभारी शशीकांत हदगल और पुलिस की संयुक्त टीम सुनिश्चित करेगी कि सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार नियमों का सख़्ती से पालन करें। मतदाता सूची में पाए गए 9,338 डुप्लिकेट नामों की भी जांच चल रही है और मतदान की तैयारियाँ अंतिम रूप ले रही हैं।
इस चेतावनी का मकसद चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कराना है, ताकि जनता का विश्वास मजबूत बना रहे और चुनावी उल्लंघनों पर कानूनी कार्रवाई प्रभावितों तक पहुँचे।

नांदेड महापालिका चुनाव 2026: भाजपा निष्ठावंत दिलीप ठाकूर ने मोदी को लिखा पत्र, कहा – हमें पार्टी ने अन्याय किया

नांदेड: 2026 के नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका चुनाव के लिए नामांकन और टिकट वितरण की प्रक्रिया में सियासी उथल-पुथल बढ़ती जा रही है। इसी बीच **भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता और निष्ठावंत नेता एडवोकेट दिलीप ठाकूर ने भाजपा नेतृत्व पर **अन्याय के गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने स्थानीय नेताओं और मेहनती कार्यकर्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया, जिसके कारण वे बगावत कर भाजपा से अलग अपक्ष उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

ठाकूर ने बताया कि उन्होंने हनुमानगड (वजिराबाद)-गाडीपुरा वार्ड से भाजपा की ओर से अधिकृत AB फार्म भरा था, लेकिन पार्टी ने उनके नाम को सूची में शामिल नहीं किया, जिससे उनका दर्जा अपक्ष उम्मीदवार बन गया। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को भेजे पत्र में अपनी पीड़ा और “निष्ठावंत कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय” को उजागर किया है।

ठाकूर ने यह भी कहा कि उनका विरोध स्थानीय “धनशक्ती” या बाहरी दबाव के खिलाफ है और वे पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनता और पार्टी कार्यकर्ता उनके संघर्ष को समझेंगे और उनका समर्थन करेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला नांदेड में टिकट वितरण और स्थानीय नेतृत्व के अधिकारियों के निर्णय पर असंतोष को दर्शाता है, जो आगामी महापालिका चुनाव के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकता

स्वाधिकारी नंदिग्राम टाईम्स (नांदेड़) के मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक शेख जहूर शेख अहेमद द्वारा सहारा डिजाइनिंग एंड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, वाजेगांव, ता. व जि. नांदेड़ में मुद्रित तथा दैनिक नंदिग्राम टाईम्स, मुल्लाह मार्केट, खवी बिल्डिंग, नगरेश्वर मंदिर, नांदेड़–431604 (महाराष्ट्र) के कार्यालय से प्रकाशित। RNI-MAHHIN/2016/69743 मोबाइल संपर्क: 9921100075 | Email: ntinfodesk@gmail.com (वाद-विवाद हेतु न्यायक्षेत्र: नांदेड़ न्याय कक्षा में।)

देश-विदेश

BREAKING

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s unchanged.

अग्रलेख: 'महाराष्ट्र में धार्मिक परिवर्तन विवाद — सामाजिक ताना-बाना पर प्रभाव और समाधान'

संपादकीय... |

1 जनवरी 2026 के महाराष्ट्र में एक बहु-चर्चित और संवेदनशील सामाजिक मुद्दा फिर उभरकर आया है — धार्मिक परिवर्तनों (Conversion) को लेकर बढ़ती चिंता और उससे जुड़ी सत्यता-अपराध की धारणा। यह केवल कानूनी मामला नहीं रहा, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना, विश्वास संरचना और सामाजिक समरसता पर असर डालने वाला मुद्दा बन गया है।

📍 क्या हुआ? घटना की सारांश जानकारी
महाराष्ट्र के अमरावती जिले में शिंगोरी गाँव के पास पुलिस ने एक केरल के पादरी और उसके साथियों को जबरन धर्म परिवर्तन और पैसे देकर लोगों को धर्म बदलवाने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि वे पहले किसी गाँव के व्यक्ति के घर गए, बाद में एक मंडप में प्रचार कर रहे थे और लोगों को आकर्षित कर रहे थे। स्थानीय शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

यह कोई पहली बार नहीं है कि धार्मिक परिवर्तन विवाद महाराष्ट्र के सामाजिक परिवेश में गर्म मुद्दा बन रहा है, लेकिन आज का यह प्रकरण राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक भावनाओं के बीच सीधी टकराहट का प्रतिनिधि बन गया है।

🤝 घाट-भाग की प्रतिक्रिया: भावनाएँ और धारणा
धार्मिक परिवर्तन केवल कानूनी धाराओं की बात न रहकर सामाजिक भावना और पहचान से जुड़ा मामला बन जाता है। इस मुद्दे को लेकर समाज के अलग-अलग वर्गों के विचार इस प्रकार हैं:

🟡 समर्थक दृष्टिकोण
कुछ लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलता है, तो इसका सम्मान होना चाहिए।

उनके अनुसार धार्मिक विचारधाराओं को अपनाने का निर्णय हर व्यक्ति के स्वायत्त अधिकार में आता है और जब तक कोई बल अभियोग नहीं है, तब तक इसे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के रूप में देखा जाना चाहिए।

🔴 आपत्ति रखने वाले
जिन लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई, उनका मानना है कि पैसे के लालच में या सामाजिक दबाव में किसी के धर्म का बदलना सामूहिक पहचान और समुदाय की सुरक्षा को खतरे में डालता है।

वे कहते हैं कि धार्मिक परिवर्तन के नाम पर अस्तित्ववादी और सांस्कृतिक प्रतिमानों को. खतरा हो सकता है, जिससे समाज में तनाव उत्पन्न हो सकता है।

यह टकराव आत्म-निर्णय बनाम सामुदायिक सन्तुलन की समस्या को दर्शाता है — जहाँ एक तरफ व्यक्तिगत अधिकार महत्वपूर्ण हैं, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक समरसता और पहचान का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

🧠 विवाद के सामाजिक पहलू — क्यों यह मुद्दा महत्त्वपूर्ण है?
1. धार्मिक पहचान और सामाजिक संरचना
महाराष्ट्र के गाँव-शहर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विविधता के साथ रहते हैं — हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट और अन्य समुदायों का साझा इतिहास है।

किसी भी समूह के प्रतीकों और पहचान में परिवर्तन (चाहे वैचारिक हो या धार्मिक), समाज के सामूहिक संतुलन में चुनौतियाँ खड़ी कर सकता है।

2. विश्वास और भ्रांतियाँ
अक्सर गाँवों में भ्रम, अफ़वाहें और डर सामाजिक तनाव को जन्म देती हैं।

ऐसे मामलों में किसी एक घटना को सामाजिक सम्प्रदायिक तनाव के रूप में देखा जाना, लोगों के सूचना-साक्षरता की कमी को भी दर्शाता है।

3. कानूनी और नैतिक अपेक्षाएँ
संविधानिक अधिकार से जुड़ी नैतिक अपेक्षा यह है कि धर्म परिवर्तन को घोर व्यभिचार और मजबूरी की स्थिति से अलग समझा जाए।

कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट होना चाहिये ताकि स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित रहें।

🧩 समाधान ढूँढने की दिशा
धार्मिक परिवर्तन जैसे मुद्दे को सामाजिक विमर्श, न्यायिक विवेक और समुदाय के साथ-साथ समझना जरूरी है। कुछ सुझाए समाधान हैं:

🔹 सूचना एवं शिक्षा
सभी समुदायों में ऐसे मुद्दों के बारे में सत्य-साक्षरता और संवेदनशीलता अभियान चलाना आवश्यक है। इससे अफ़वाहें और डर कम होंगे और लोग तथ्यों के आधार पर सोचेंगे।

🔹 स्थानीय संवाद मंच
गाँव और शहर स्तर पर धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच संवाद मंच स्थापित किए जाने चाहिए, जहाँ सामूहिक चिंताओं पर खुलकर चर्चा हो सके।

🔹 न्यायिक नीति की स्पष्टता
कानूनी नीति को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना चाहिए कि स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन और जबरदस्ती/लालच से परिवर्तन में क्या अंतर है, और किसके अंतर्गत क्या दंडनीय अपराध हैं।
यह सामाजिक विश्वास को मज़बूत करेगा और निर्णय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा।

📌 निष्कर्ष
महाराष्ट्र जैसे सांस्कृतिक रूप से विविध राज्य में धार्मिक परिवर्तन विवाद सिर्फ कानून का मसला नहीं है — यह मानव अधिकार, सामुदायिक पहचान, सामाजिक सहिष्णुता और लोकतंत्र के मूल्यों का संतुलन है। यदि हम इसी तरह बातचीत, समझ और मानव-केन्द्रित नीतियाँ अपनाएँ, तो ऐसे विवाद विवेकपूर्ण समाधान की दिशा में बदल सकते हैं।

अमेरिका का बाहुबली MQ-9 रीपर ड्रोन अफगानिस्तान में हुआ ढेर, पाकिस्तान की भी खुल गई पोल!

काबुल: अफगानिस्तान के सुरक्षाबलों ने कथित तौर पर मैदन वर्दक प्रांत में एक ड्रोन एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान समर्थकों ने इसे अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन बताया है। इसके पकिस्तान से लॉन्च किए जाने की संभावना है। गुरुवार (1 जनवरी) की सुबह अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में यह गिरा है। तालिबान समर्थक सोशल मीडिया यूजर्स ने क्रैश हुए अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं। हालांकि ड्रोन के गिरने के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

अफगानिस्तान में गिरे इस रीपर ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इसे गुपचुप तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे पाकिस्तानी एयरबेस से लॉन्च किया गया था।

पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर अमेरिकी एजेंसियों की मौजूदगी से इनकार करता रहा है। इसके जैकोबाबाद या शम्सी जैसे अमेरिकी इस्तेमाल वाले पाकिस्तानी ठिकानों से लॉन्च किए जाने की संभावना है। ऐसे में इससे पाकिस्तान की भी पोल खुलती है।

अमेरिका को झटका
अफगानिस्तान में यह ड्रोन गिरना अमेरिका के लिए झटका है। बीते साल यमन के हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने अक्टूबर, 2023 से 22 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं।

यमन के बाद अफगानिस्तान में गिरने से अमेरिका के इस ताकतवर हथियार पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अमेरिका के इस ड्रोन को बेहद सटीक माना जाता है। अमेरिका के इस ड्रोन की मारक क्षमता बेहद सटीक है। MQ-9 रीपर में 8 हेलफायर मिसाइल और 1700 किलो तक बम ले जाने की क्षमता है। इससे यह दुश्मन के टैंकों, ठिकानों और सैनिकों को तबाह कर सकता है। ये 50 हजार फीट की ऊंचाई से दुश्मन का पता लगा लेता है। भारत ने भी अमेरिका से इन ड्रोन पर डील की है।

भारत का अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारत को 31 MQ-9B ड्रोन मिलेंगे। ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस (HALE) क्षमता वाले हैं। भारत को MQ-9B ड्रोन साल 2029 से मिलना शुरू होंगे। साल 2030 तक सारे 31 ड्रोन भारत को मिल जाएंगे।

WORLD NEWS | पाकिस्तान ने भारत को दी अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी,

पाकिस्तान ने भारत को दी अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी, भारत ने भी सौंपी लिस्ट, जानें वजह

इस्लामाबाद: भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी एक-दूसरे को दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने गुरुवार को यह बताया है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली ने अपने-अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट का आदान-प्रदान किया। यह साल 1988 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत हर साला होने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे गुरुवार को पूरा किया गया।

ताहिर अंद्राबी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी की लिस्ट आज ऑफिशियली फॉरेन ऑफिस में इंडियन हाई कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव को सौंप दी गई।

भारत ने भी आज ही नई दिल्ली में हमारे हाई कमीशन के साथ इंडियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट शेयर कर दी है। कैदियों की लिस्ट भी सौंपी गई
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी के बारे में जानकारी के अलावा कैदियों की लिस्ट का भी एक्सचेंज किया है। भारत ने अपनी कस्टडी में मौजूद पाकिस्तानी कैदियों की लिस्ट दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को दी है।

पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन को 257 इंडियन कैदियों (58 सिविल और 199 फिशरमैन) की लिस्ट सौंपी है। कॉन्सुलर एक्सेस एग्रीमेंट 2008 के फॉलोइंग में दोनों साइड जनवरी और जुलाई को एक-दूसरे की कस्टडी में मौजूद कैदियों की लिस्ट शेयर करनी होती है।
क्यों दी न्यूक्लियर ठिकानों की जानकारी
भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के प्रतिबंध से जुड़ा समझौता है।

भारत ने भी सौंपी लिस्ट

इसी के तहत लिस्ट साझा की गई है। यह समझौता 31 दिसंबर 1988 को साइन किया गया था और 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ। समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी एक-दूसरे को देना जरूरी है। पहली बार यह सूची 1 जनवरी 1992 को साझा की गई थी।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बार फिर सिंधु जल संधि (IWT) पर भी बात की गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत पश्चिमी नदियों पर एकतरफा कोई भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपनी सीमित छूट का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अंद्राबी ने ये बातें भारत की ओर से कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट के दुलहस्ती स्टेज-II हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को मंजूरी से जुड़े सवाल पर कही।

भारतीय विदेश मंत्री खुद मेरे पास आए, जयशंकर से हाथ मिलाकर पाकिस्तानी सादिक ने बघारी शेखी, बड़ा दावा

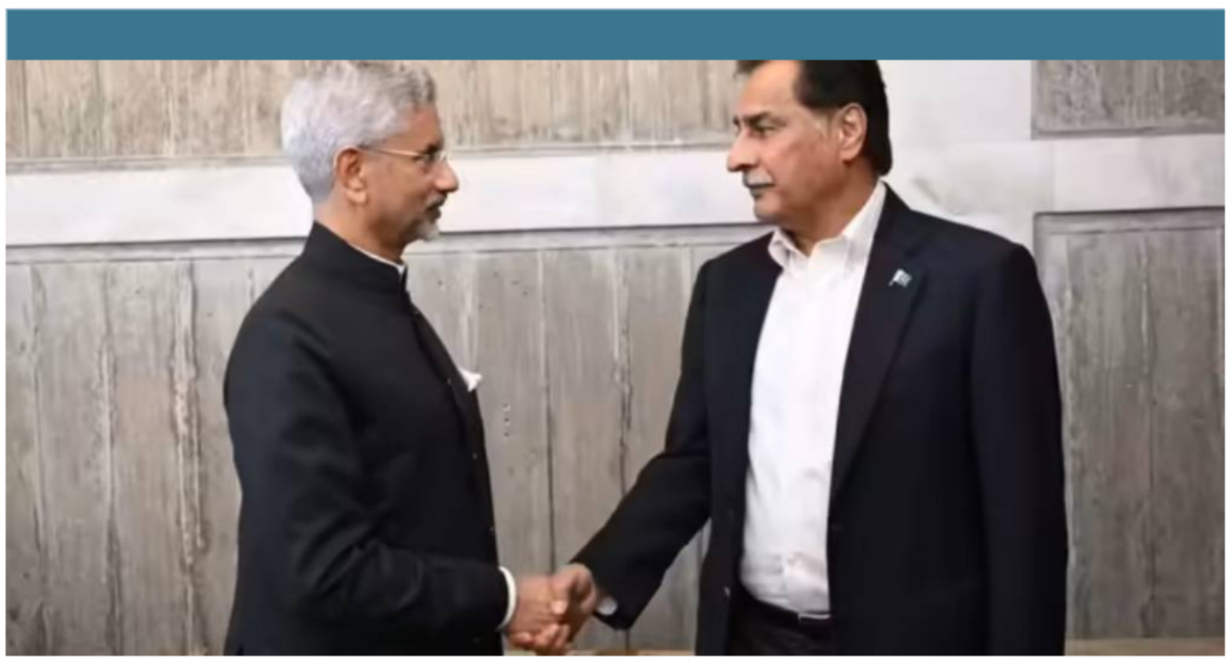

इस्लामाबाद: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (संसद) के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात हुई है। दोनों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने ढाका पहुंचे थे। इसी दौरान बुधवार को दोनों नेताओं ने एक मौके पर हाथ मिलाया और एक-दूसरे का अभिवादन किया। इस तस्वीर ने दुनिया का ध्यान खींचा है क्योंकि बीते साल मई में हुए सैन्य संघर्ष के बाद भारत-पाकिस्तान के दो बड़ी नेता पहली बार इस तरह से मिले हैं। इस मुलाकात पर सादिक ने कहा है कि जयशंकर खुद चलकर उनकी ओर आए थे।

जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने गुरुवार को कहा कि ढाका में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर ने ही उनसे आकर मुलाकात की। उन्होंने कहा, ' जयशंकर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल संसद के वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। रूम में पाकिस्तान के अलावा मालदीव, नेपाल, भूटान और बांग्लादेशी अधिकारी पहले से मौजूद थे।'

मेरे पास आकर हाथ मिलाया
सादिक ने आगे कहा, ' जयशंकर ने रूम में आने के बाद दूसरे प्रतिनिधिमंडलों को हैलो किया और फिर मेरे पास आकर हाथ मिलाया। उस वक्त मैं बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से बात कर रहा था। तभी मेरे पास आकर उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं अपना परिचय देने लगा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पहचानता हूं। आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है।'

सादिक ने यह भी कहा जयशंकर कोई छुपकर मुझसे मिलने नहीं आए थे, वो जानते थे कि वह क्या कर रहे हैं। जयशंकर के साथ कैमरे थे, जिससे पता चलता है कि जयशंकर को पूरी जानकारी थी कि इस बातचीत को रिकॉर्ड किया जाएगा और मीडिया में रिपोर्ट किया जाएगा। उन्हें ठीक से पता था कि वह क्या कर रहे हैं और इसे मीडिया कवर करेगा।
जयशंकर होशियार नेता
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर ने कहा कि उन्हें लगा कि जब जयशंकर और वह हाथ मिला रहे थे तो कमरे में सभी की नजरें उनकी बातचीत पर ही लगी हुई थीं। अयाज सादिक ने जयशंकर को एक मंझा हुआ राजनेता बताया जो उस पल की अहमियत और उसके असर को बखूबी समझ रहे थे।